country like the telephone services. If so, what are the Governemnt planstime table by which all the villages will be covered;

(b) how many out of the total villages in Haryana have been provided with post offices and by when the remaining villages will be covered; and

(c) how many type of postal services are being provided by the Department at the village level and what are the pattern of the various services being provided?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Post Offices in rural areas are opened as per norms, subject to availablity of funds and Plan targets. Norms are as follows:—

	Normal area	Hilly tribal, desert and inaccessible areas
Population	3000	1000
Distance from the nearest Post Office	3 Kms.	3 Kms.
Income to cost	33.16%	15%

(b) In Haryana, 2270 villages, out of 6757 have already been provided with post offices. Remaining villages will be coverd in course of time, subject to their fulfilling the norms and availability of resources and Plan targets.

(c) Postal services, namely, collection and delivery of mail, registration, parcel, insured, money order and Savings Bank facility, are being provided at the vilage level and the pattern of these services are through either extra departmental branch post office or departmental sub post office.

Shifting of Telephones

2677. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the cases of transfer of telephone connections in Delhi have been delayed beyond the usual time;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to simplify the procedure of shifting of telephone connections;

(d) if so, by when; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir. Noarmally cases relating to transfer of telephones are disposed of within the usual time subject to submission of proper documents by the subscriber.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) and (d) Procedure for shifting has been simplified in respect of telephones provided under OYT-Scheme by permitting the shift if its date of registration has been covered in the exchange are where it is required to be shifted or it has worked for a period of at least six months in the exchange area from where it is required to be shifted.

In the case of telephone connections provided under Tatkal Category, local shift is permitted without any pre-condition.

(e) Does not arise in view of (c) and (d) above.

Post Offices without Public Telephone Facility in Gujarat

2678. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of post offices£ub-post offices in Gujarat without public telephone facility; and

(b) the details of steps being taken to provide this facility in all post offices/sub-post offices?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The total number of post offices/sub-post offices in Gujarat without public telephone facility is 6689.

(b) Government have adopted a policy to provide public telephone facility to al villages including those in Gujarat State progressively by March 1997, subject to availability of resources. Post offices are one of the suggested locations were these public telephones are being provided. There is no separate plant to provided telephone facility to post offices^ub post offices.

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन

2679. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रों के सांसदों से परामर्श किया है, जहां जिला टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गई हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह समिति कब तक गठित कर दी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन करते समय, संचार राज्य मंत्री के कार्यालय में, संसद सदस्यों, विभिन्न स्थानीय निकायों और जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

(ख) उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर की टेलीफोन सलाहकार समिति के गठन के स्थान पर कानपुर, बरेली, देहरादून और लखनऊ में हाल ही में, क्षेत्रीय टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) ये टेलीफोन सलाहकार समितियां शीघ्र ही गठित की जाएंगी।

दूरसंचार विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जाना

2680. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को संतोषजनक टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में अन्य क्या-क्या तरीके अपनाएगी;

(घ) क्या गुजरात दूरसंचार परिमंडल ने गत दो वर्षों के दौरान ऐसा कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मानीटरिंग कार्य निष्पादन तथा सर्वेक्षण कार्य अनेक प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है जिसका विस्तृत उल्लेख नीचे किया गया है।

(1) मुख्यालय से पानीटरिंग संगठन देश भर में प्रमुख प्रणालियों को नियमित आधार पर मुख्यालय स्तर पर मानीटर करता है।

(2) फील्ड कार्यालयों में एक एम०आई०एस० संगठन है जो कि प्रणाली के कार्य-निष्पादन का सतत रूप से मानीटरिंग करता है।

(3) इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के माध्यम से छमाही आधार पर सभी मेजर और माइनर टेलीफोन जिलों के कार्य निष्पादन को मानीटर किया जाता है।

(4) प्रमुख व्यक्तियों के सामाजिक आडिट पैनल के माध्यम से मानीटरिंग करना। यह पैनल सर्किलों का दौरा करता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करता है।

(घ) और (ङ) सर्किल एम०आई०एस० संगठन नियमित रूप से मानीटर करता है जिसके आधार पर मुख्यालय संगठन को मासिक कार्य-निष्पादन के आंकड़े भेजे जाते हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान आई०एम०आर०बी० (इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो) ने अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और जामनगर का दो बार सर्वेक्षण किया था।